समाज विज्ञान शोध केन्द्र

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

राष्ट्रीय संगोष्ठी

Social Development and Social Exclusion: Changing Context and Emerging Challenges

(सामाजिक विकास एवं सामाजिक अपवर्जन – बदलते संदर्भ एवं उभरती चुनौतियाँ)

(18 – 19 मार्च, 2017)

विकास एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसकी निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। अर्थशास्त्री इसे आर्थिक उत्पादकता से परिभाषित करते हैं, समाजशास्त्री इस शब्द का का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में करते हैं, राजनीतिक विचारक इसे लोकतंत्रीकरण, राजनीतिक क्षमता अथवा विस्तारशील सरकार के रूप में करते हैं जबकि प्रशासक इसे प्रशासनिक दक्षता, कुशलता एवं क्षमता के रूप में स्वीकार करते हैं तथापि कहा जा सकता है कि विकास की परिभाषा जीवन की गुणात्मकता के रूप में जीवन की प्रगति के रूप में दी जा सकती है, जिसके द्वारा परम्परागत स्थिति से आधुनिक स्थिति पर आया जाता है जो सदैव राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति की ओर निर्देशित होती है। अतः विकास का एक निश्चित लक्ष्य होता है जो कि मानवीय विकास के संदर्भ से अनिवार्य रूप से जुडा है। विकास के अन्तर्गत सामाजिक विकास एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसके अंतर्गत वह प्रक्रिया आती है जिसके माध्यम से समाज में रहने वाले नागरिकों के जीवन को गुणात्मक तौर पर सुधारा जा सकता है। अतः सामाजिक विकास एक अभीष्ट दिशा की ओर रचनात्मक पिछड़ेपन का विपरीतात्मक स्वरूप हो सकता है। उसमें बुद्धि विन्यास तथा ज्ञानोदय, मानव तथा मानव प्रकृति को समझने की बेहतर क्षमता तथा समाज में गुणात्मक परिवर्तन करने की बेहतर क्षमता का विकास अर्न्तनिहित होता है परंतु यह सामाजिक विकास तभी संभव है जबकि इसमें समाज के सभी वर्गों का विकास अर्न्तनिहित है और विशेषकर समाज के ऐसे वंचित वर्गों का जो कि विकास की मुख्य धारा में न होकर हाशियें पर हैं इनमें समाज का महिला वर्ग, श्रमिक वर्ग, दलित वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विमंदित वर्ग आदि हो सकते हैं और जैसा कि विदित है कि समाज का समग्र विकास उस समाज के समस्त वर्गो के विकास पर ही निर्भर करता है ऐसे में समाज के वंचित वर्गों का विकास अपरिहार्य हो जाता है। भारत विश्व का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश है। प्रत्येक लोकतान्त्रिक देश के अपने मूल्य होते हैं। जनता को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करना लोकतंत्र का सर्वप्रमुख मूल्य होता है। समाजिक न्याय राज्य की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्तमान समय तक भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं चूंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व नागरिकों को न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना होता है ताकि समाज के वंचित, पीडित एवं असहाय वर्ग को सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके एवं विकास की मुख्य धारा में जोड कर देश के विकास में उनके योगदान को सुनिश्चित किया जा सके लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने में अनेक समस्याएं भी है जो किन्हीं चुनौतियों से कम नहीं है।

अतः कहा जा सकता है कि समाज के सभी वर्गों के विकास के बिना समाज अथवा राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी पृष्ठभूमि में विषय की महत्ता एवं प्रासंगिकता के दृष्टिगत समाज विज्ञान शोध केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा **"Social Development and Social Exclusion : Changing Context and Emerging Challenges" (सामाजिक विकास एवं सामाजिक अपवर्जन – बदलते संदर्भ एवं उभरती चुनौतियाँ)** विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का दिनांक 18 व 19 मार्च, 2017 को आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य बदलते परिदृश्य में सामाजिक विकास एवं वंचित वर्गों के विकास के समक्ष उपस्थित विभिन्न संभावनाओं एवं चुनौतियों के साथ–साथ इस दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं रणनीतियों के साथ–साथ उनके प्रभावों, चुनौतियों एवं समाधानों पर विचार–विमर्श एवं चिंतन करना है।

संगोष्ठी के प्रस्तावित उपशीर्षक इस प्रकार हैं :–

1. सामाजिक विकास का ऐतिहासिक एवं अवधारणात्मक पक्ष
2. विकास की अवधारणा एवं इसके विविध आयाम
3. सामाजिक विकास एवं वंचित वर्ग
4. न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं के लिए विकासात्मक कार्यक्रम एवं रणनीतियाँ
5. आधारभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचनात्मक विकास
6. वंचित वर्गों का विकास एवं भूमण्डलीकरण का प्रभाव
7. सामाजिक आन्दोलन और सामाजिक अपवर्जन
8. सामाजिक विकास और अपवर्जन की उभरती प्रवृत्तियाँ और विकासमान चरित्र
9. सामाजिक गतिशीलता और बदलते प्रतिमान
10. सामाजिक अपवर्जन की आर्थिक–राजनैतिक गतिकी
11. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विकास एवं सामाजिक अपवर्जन के बदलते संदर्भ
12. सामाजिक अपवर्जन के विकास के समक्ष चुनौतियाँ एवं उनके समाधान

- **शोध सारांश (Abstract) भेजने की अन्तिम दिनांक – 16 मार्च, 2017**
- **पंजीकरण शुल्क**

  शिक्षकों हेतु – 800 रू.
  शोधार्थियों हेतु – 600 रू.
  विधार्थियों हेतु – 300 रू.

Raka Singh
डॉ. राका सिंह
संगोष्ठी संयोजक एवं निदेशक,
समाज विज्ञान शोध केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
मोबाईल नं. 9928367935,
ईमेल – *ssrcuorjpr@gmail.com*